(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस कारण हरियाणा को प्रति वर्ष कितना नुकसान हो रहा है;

(घ) क्या सरकार इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार इस परियोजना को पूरा करने का कार्य बार्डर कन्स्ट्रक्शन फोर्स को सौंपने का विचार रखती है;

(छ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। रावी व्यास प्रणाली का कुछ जल विभिन्न कारणों से जिसमें सतलुज यमुना संपर्क नहर का पूर्ण नहीं होना भी सम्मिलित है, पाकिस्तान में प्रवाहित हो रहा है।

(ग) सतलुज यमुना संपर्क नहर के पूरा न होने के कारण, रावी व्यास जल अधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1980-85 के दौरान हरियाणा विद्यमान नहर प्रणाली द्वारा अपने 2811 घन मिलियन मीटर हिस्से में से केवल 71 प्रतिशत जल का उपयोग करने में समर्थ रहा है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार नहर के पूरा न होने के कारण हरियाणा को कृषि उत्पादन नहीं बढ़ाने की वजह से 100 करोड़ रुपये की हानि हो रही है।

(घ) और (ङ) पंजाब सरकार को सतलुज यमुना संपर्क नहर के शेष कार्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त अभिकरण/अभिकरणों को लगाने की सलाह पहले ही दी जा चुकी है। परियोजना को पूर्ण करने के समय का निर्धारण पंजाब सरकार द्वारा लगाये जाने वाले नए अभिकरण/अभिकरणों के स्वरूप और क्षमता पर निर्भर करेगा।

(च) से (ज) सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना पंजाब सरकार के पास निर्माणाधीन है। किसी उपयुक्त अभिकरण/अभिकरणों को कार्य सौंपने के लिए आवश्यक कार्रवाई के बारे में पंजाब सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

केलो बहु-उद्देश्यीय सिंचाई परियोजना को स्वीकृति

2278. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में प्रस्तावित "केलो बहु-उद्देश्यीय सिंचाई परियोजना" को स्वीकृति अभी दी जानी शेष है;

(ख) राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के समाधान के लिए किन मुद्दों पर अपना स्पष्टीकरण भेजा है;

(ग) उक्त परियोजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तिम स्वीकृति दिए जाने के मार्ग में क्या बाधाएं हैं; और

(घ) इस परियोजना पर वर्ष 1991-92 तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के अन्तर्गत नियोजित कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) परियोजना के जलविज्ञान, सिंचाई आयोजना, जल प्रबंध, फसल आयोजना, बांध, द्वारों और नहरों का डिजाइन, संयंत्र आयोजना, लागत अनुमान, पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाएं तथा भूजल पहलुओं को अन्तिम रूप दिया गया है। राज्य सरकार को पर्यावरणीय और वन दृष्टिकोण से पर्यावरण और वन मंत्रालय से

और कोयला खानों की जलमग्नता के बारे में कोयला मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है।

(घ) मार्च, 1992 तक इस परियोजना पर कोई व्यय नहीं किया गया।

किसी विशेष परियोजना पर लगाए गए व्यक्तियों का रिकार्ड केन्द्र में नहीं रखा जाता है।

INDO-Nepal River Projects

2279. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE:

SHRI V. NARAYANASAMY:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has not fulfilled its commitments regarding Indo-Nepal river projects particularly Gandok and Kosi Canals;

(b) if so, what are the details of India's commitment to Nepal; and

(c) what are the reasons for not fulfilling the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MNISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c) India, as per its commitmtnts, has completed Kosi and Gandok canals for irrigating 0.395 lakh hectares and 0.44 lakh hectares in Nepal respectively. The maintenance of the canals is being carried out as per site requirements.

Restructure of Irrigation Department

2280. SHRI MATAN SINGH: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the administration of irrigation department has become unwieldy and Government propose to cut down administrative cost by restructuring it; and

(b) if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Ongoing Irrigation Projects in the States

2281. SHRI RAMJI LAL: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the minor and major ongoing irrigation projects as on 28th February, 1993 state-wise;

(b) whether the amount allocated for irrigation projects has been continuously reduced during the last thret years;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) the amount sought from world Bank for irrigation purposes during 1992-93 till date and its allocation state-wise; and

(e) its likely impact on the irrigation facility in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) State-wise list of major, medium and extension, renovation and modernisation schemes spilling into VIII Plan is given in the statement attached (Statement-I) (see below). The information about minor irrigation schemes is not maintained at the Centre.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) A statement is attached (Statement-II) (*See* below)

(e) While the projects have been taken up the State Governments on their own, World Bank's assistance constitutes only a fraction of the total expenditure on these projects.